बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

तारांकित प्रश्न
वर्ग – 2

22 फाल्गुन, 1939 (श.)
मंगलवार, तिथि ----------
13 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 17

1.	स्वास्थ्य विभाग	....	....	10
2.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	....	....	06
3.	ऊर्जा विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**17**

महिला चिकित्सकों का पदस्थापन

* 192. **प्रो. नवल किशोर यादव** एवं **श्री सी.पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में महिला चिकित्सक नहीं है, जिससे महिला मरीजों को चिकित्सा कराने में परेशानी हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि इस अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक डॉ. किरण की प्रतिनियुक्ति, पंडारक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कर दी गई है और उनके स्थान पर महिला चिकित्सक नहीं दिये गये हैं, जिससे बाढ़ अनुमंडल में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में आये महिला मरीजों को इलाज एवं प्रसव कराने में कठिनाई हो रही है, फिर भी अस्पताल प्रशासन मौन है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित अस्पताल में महिला चिकित्सकों को पदस्थापित/प्रतिनियुिक्ति करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

इमरजेंसी कैडर बनाने पर विचार

* 193. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य के नौ मेडिकल कॉलेजों में डाक्टरों का इमरजेंसी कैडर बनाने का मामला काफी समय से लंबित है;

(ख) क्या यह सही है कि इमरजेंसी कैडर बनाने के संबंधित नियमावली पांच वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में लंबित पड़ी हुई है;

(ग) क्या यह सही है कि इमरजेंसी कैडर नहीं बनाने के कारण आए दिन अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो जाती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के नौ मेडिकल कॉलेजों में डाक्टरों का इमरजेंसी कैडर शीघ्रातिशीघ्र बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

मूल्य निर्धारित

***** 194. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बाजार में बिकने वाला हर बोतलबंद पानी या तथाकथित मिनरल वाटर सौ प्रतिशत शुद्ध नहीं है और बावजूद इसके प्रत्येक बोतल बंद पानी 20 (बीस) रु. प्रति बोतल बाजारों में बेचा जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और इसके तहत नियमों को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है;

(ग) क्या यह सही है कि बोतलबंद पानी की जांच एवं उसके निर्धारित मूल्य हेतु सरकार द्वारा अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, जिसके कारण सात से दस रुपये प्रति लीटर बोतलबंद पानी को 20 (बीस) रुपये में बेचा जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बोतलबंद पानी बेचने वाली कंपनियों के उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरूप हैं या नहीं, क्या सरकार इसकी जांच कराकर बाजार में बेचे जाने वाले बोतलबंद पानी की जांच कराते हुए योग्य कंपनियों के लिए मूल्य निर्धारित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल की व्यवस्था

***** 195. **श्री कृष्ण कुमार सिंह, डा. दिलीप कुमार जायसवाल, श्री राधाचरण साह** एवं **प्रो. संजय कुमार सिंह** :
क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शुद्ध पेयजल आम लोगों का संवैधानिक अधिकार है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के 13 जिलों में आर्सेनिक युक्त, 11 जिले में फ्लोराइड युक्त एवं 9 जिलों में आयरन युक्त पानी है;

(ग) क्या यह सही है कि प्रदूषित पानी पीने से लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के नागरिकों को शुद्ध पेयजल दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

सुविधा मुहैया

***** 196. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के नवादा प्रखंड स्थित ओढ़नपुर गांव में करीब ढाई वर्ष पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सरकारी लागत से पूर्ण रूप दिया गया और यहां तक कि जेनरेटर आदि की भी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये गये हुए ढाई वर्ष बीत जाने के बाद अभी तक उसके विभाग ने उसे अपने अधीनस्थ नहीं किया है जिसके कारण गरीब जनता उक्त केन्द्र के लाभ से वंचित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केद्र को अपने अधीन लेते हुए गरीब जनता को इसकी सुविधा मुहैया कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

पेयजल की व्यवस्था

***** 197. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत बंजरीया लक्ष्मण चौक के पास विभागीय चापाकल लगा था जो अब खराब हो चुका है। लक्ष्मण चौक के पास अतिपिछड़ा, अकलियत एवं गरीब लोग, जो रोजमर्रे का काम कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थल पर खराब चापाकल के संबंध में पी.एच.ई.डी. विभाग को वहां की जनता ने कई बार अवगत कराया है तथा चापाकल को चालू करने हेतु आवेदन देने के उपरांत विभागीय कर्मचारियों द्वारा शीघ्र चालू कराने का अश्वासन दिया गया था;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त स्थल पर विगत 2-3 वर्षों से खराब, बंद पड़े चापाकल चालू करा कर स्थानीय गरीब, दलित, अतिपिछड़ों एवं अकलियत के लोगों को स्वच्छ पेयजल सरकार उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नीति नहीं

*198. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सात निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल उपलब्ध कराने की योजना है;

(ख) क्या यह सही है कि गया जिले के नगर प्रखंड के ग्राम बीथो में जल मीनार का निर्माण किया गया है, किन्तु अब तक पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण जल मीनार के संचालन के लिए प्रबंधन की नीति नहीं बनी है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त जल मीनार मृतप्राय हो चुका है जिससे हर घर नल का जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है;

(घ) क्या यह सही है कि प्रबंधन की नीति और समुचित संचालन नहीं होने के कारण उपद्रवियों के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित जल मीनार से नियिमत जल की आपूर्ति कबतक सुनिश्चित करना चाहती है और अभी तक प्रबंधन की नीति नहीं बनाने वाले पदाधिकारियो के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है ?

योजनाओं का लाभ

* 199. **श्री सी.पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार सूबे में सुशासन के कार्यक्रम 2020 और मुख्य रूप से सात निश्चय के क्रियान्वयन की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता प्रखंड के विशौनी गांव में सात निश्चयों के कार्यक्रम की कोई योजना चालू नहीं की गई है। गांव को नल से जल योजना का लाभ अति आवश्यक है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त गांव में लगे चापाकल या तो खराब हैं या उनका पानी प्रदूषित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जिला के उक्त गांव को प्राथमिकता के आधार पर नल से जल योजना का लाभ देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पानी उपलब्ध

***** 200. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला के बड़हारा प्रखंड में ग्राम मौजमपुर में जलपूर्ति की व्यवस्था के लिए जल मीनार की व्यवस्था है;

(ख) क्या यह सही है कि इस जल मीनार से प्रखंड के 42 गांव के करीब लोग लाभान्वित होते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि समय-समय पर ऑपरेटर के द्वारा जल मीनार से पानी चालू नहीं देने पर ग्रामीणों में आक्रोश रहता है और ग्रामीणों के द्वारा शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं की जाती है जिसके कारण ग्रामीण जनता को कठिनाई होती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई करते हुए समय पर ग्रामीण जनता को पानी सरकार उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रक्रिया पूर्ण

***** 201. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि अमृत योजना के तहत मरीजों को सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में 995 दवा दुकान खोले जाने की योजना है;

(ख) क्या यह सही है कि योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में ढाई किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में पांच किलोमीटर की दूरी पर जेनरिक दवा दुकान खोली जानी है;

(ग) क्या यह सही है कि इसके लिए सरकार खुदरा दवा दुकानदारों को लाईसेंस दे रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अबतक कितने जिलों में जेनरिक दवा दुकान खोलने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और सरकार कबतक पूरे राज्य में प्रक्रिया पूर्ण कर लेना चाहती है ?

चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति

*202. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर अनुमंडल मुख्यालय में बनाए गए रेफरल अस्पताल को चालू तो कर दिया गया लेकिन मानक के अनुरूप आधारभूत संरचना समेत चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों का पदस्थान नहीं होने से लोगों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त रेफरल अस्पताल में एक भी महिला चिकित्सक नहीं है जबकि सरकारी स्तर पर प्रत्येक अस्पताल में महिला चिकित्सक पदस्थापित करना अनिवार्य है;

(ग) क्या यह सही है कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिल पा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जयनगर अनुमंडल रेफरल अस्पताल में आधारभूत संरचना सहित महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति

* 203. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नी सैदपुर प्रखंड में छः अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं परंतु किसी में भी डाक्टर की प्रतिनियुक्ति नहीं रहने के कारण मरीजों की चिकित्सा में काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र में डाक्टर की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नया पम्प की व्यवस्था

***** 204. **श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर नगर परिषद वार्ड सं.-23 मिडिल स्कूल में जो विभागीय पम्प लगा है, उसकी स्थिति काफी दयनीय है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पंप से पानी का बहाव काफी कम प्रेशर से गिरता है और अक्सर उससे गंदा पानी भी आता है;

(ग) क्या यह सही है कि गर्मी के दिनों में अक्सर पम्प खराब हो जाने के कारण 20 हजार की आबादी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त पम्प के बगल में ही जनकधारी लाल रोड में, जो पूर्व से पम्प खराब है, उसका जगह पर नया पम्प लगाना चाहती है जिससे 20 हजार की आबादी को स्वच्छ पानी मिल सके;

(ड़) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खराब पम्प की जगह पर नया पम्प लगाना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

निलंबन से मुक्त

*****205. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, अदक्ष खलासी, आरा, विद्युत अंचल, आरा को विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त करार दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने संचिका के प्रत्येक टेबुल पर निष्पादन की अवधि निर्धारित की है परंतु श्रीवास्तव के मामले से संबंधित संचिका अधीक्षण अभियंता, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन, आरा अंचल के श्री बी.के. चौधरी तीन माह से अपने पास रखे हुए हैं जिससे उक्त कर्मी आज तक निलंबित हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कर्मी को कबतक निलंबन मुक्त करेगी ?

अतिरिक्त भवन

*206. **श्री सच्चिदानन्द राय** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड दिघवारा के ग्राम बस्तीजलाल में मात्र एक कमरे का अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में जमीन उपलब्ध होने के बावजूद समुचित भवन का निर्माण नहीं हो सका है;

(ग) क्या यह सही है कि राजपथ 19 में अक्सर सड़क दुघर्टनाओं में जानें जाती हैं जिन्हें इस अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र में समुचित व्यवस्था करा कर बचाया जा सकता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यहां आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

स्वास्थ्य केन्द्र की घेराबंदी

*207. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड के बाखरपुर पूर्वी/पश्चिमी पंचायत में अवस्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र की घेराबंदी अब तक नहीं की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि घेराबंदी नहीं होने के कारण वहां की जमीन अतिक्रमित हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र की घेराबंदी कबतक कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

वेतन का भुगतान

***208. श्री राजेश राम** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु दृढ़ कटिबद्ध है तथा इसके लिए सभी आवश्यक संरचनाओं को पूरा किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि पश्चिम चंपारण जिले के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापित कर्मियों का वर्षों से वेतन लंबित है जिससे उनके समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है;

(ग) क्या यह सही है कि सिविल सर्जन पश्चिम चंपारण बेतिया के पत्रांक-2470, दिनांक-18.12.2017 के द्वारा कर्मियों के बकाया वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त आवंटन से संबंधित प्रतिवेदन भेजा गया है जिसपर अबतक निर्णय नहीं हो सका है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पश्चिम चंपारण जिले के स्वास्थ्य कर्मियों के वर्षों से लंबित वेतन का भुगतान शीघ्र कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

पटना
दिनांक 13 मार्च, 2018 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्